share with the Government a very startling piece of information. This is a very startling information. She says that the number of transgenders in India is actually seven or eight times more than the figures given by the Census. Now this is a very, very important study which had to be looked into by any Expert Committee or anyone formulating a national policy in this direction or for this subject.

Therefore, finally, while concluding my brief intervention on this subject, I would say, the litmus test of any democracy is the treatment given to its minorities -- and they are a very microscopic oppressed discriminated minority of our system. Therefore, the system has to be both sensitive and sensible towards their problems and the issues. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Husain Dalwai could not be present when I called him to introduce the Bill. He says, he wants to go early. Does the House agree if I allow him to just introduce the Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Yes, Mr. Dalwai.

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2015

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But this should not be taken as a precedent. Shri K.T.S. Tulsi, not present; Shri Biswajit Daimary, not present, Dr. M.S. Gill.

The Rights of Transgender Persons Bill, 2014–Contd.

DR. M.S. GILL (Punjab): Thank you, Sir. In my thinking, this is one of the most important Bills which has come up on a Friday in the last many, many years. ...*(Interruptions)*... I am speaking now. Please. ...*(Interruptions)*... Just give me a few minutes.

Sir, I think it is one of the most important Bills that has come up on a Friday in this House for many, many years. I want to compliment Mr. Siva for bringing it forward.

[Dr. M.S. Gill]

I have read it twice and it is very comprehensive in the detailing of what they have put in. In order to get the attention of the two Parties, DMK and AIADMK, I will also compliment the Tamil Nadu Government and both Amma and Mr. Karunanidhi. I hope my friend is also listening to me. ...*(Interruptions)*...Sir, this is a grave problem and a sad comment on India's civilized behaviour. Many Members have already put down what it relates to, how many people are affected, how many in the rural areas and how many in the urban areas. I tend to agree that actually, the number is much greater than what is put out in the census. I see that there was a book that was quoted. Therefore, it is something, which we, as a civilized country, must address, and address without delay.

Sir, the Bill has laid out everything -- the need for a National Commission, the need for State Commissions, courts with adequate authority, directions to Magistrates, and so on. When we meet these people, children, adults, men and women, at the traffic lights, we look the other way. If I can say so, sadly, almost like in the case of Leprosy, we push away from these people. कोई भी हिज़ड़ा यदि नज़दीक जाए, तो हम उसे दूर करते हैं। This is the truth in India. They have the same rights as you and me. The Constitution has the same duty to protect them as much as you and me. But this is not happening. I compliment the Tamil Nadu Government -- both Parties, don't worry about that – both Amma and Mr. Karunanidhi...*(Interruptions)*... I really mean it, because Tamil Nadu does many progressive things; forget about the politics. And, it seems to me that this is a legislation which Tamil Nadu has done seven-eight years ago; no other State in India has done it. Tell me if any other State has done it.

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, Maharashtra.

DR. M. S. GILL (Maharashtra): Okay. We compliment you too, if you have done it. ...*(Interruptions)*...

Therefore, the States need to pass such legislation. The Centre, Sir, must own this Bill. Normally, very few bills are accepted by the Government. They say, Mr. Nehru some times accepted them; maybe some other person had done it some time in the last many decades. This is a Bill that the Government must own and thank Mr. Siva for. They must pass a sensible legislation quickly. It will do credit to the new Government of India and their social concerns. We need, urgently, to put this together. The Bill itself has laid out all the details of what needs to be done, how it is to be done, their legal rights, financial help and their protection. They all need protection. People very easily, as a mob, misbehave with individuals in India on many occasions, and certainly जो बेचारे हिज़ड़े हैं, उनका तो करते हैं या करेंगे। गांव में ज्यादा करेंगे या शहर में करेंगे। Somebody has to look after them; somebody has to protect them. And that is the duty of the

Government. It is the duty of the Constitution. We are a House of Elders. We should be recommending unanimously to the Government, to own this Bill and immediately take it up for passage in the next Session. That is what it should be doing. They would get unanimous support in both the Houses. This is one Bill that nobody will quarrel over. I think, that is important.

That is all the request that I want to make, Sir. Thank you.

श्री मनसुख एल. मांडविया (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, श्री तिरुची शिवा जी ट्रांसजेंडर के लिए जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसका इसलिए अनुमोदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में सभी जीवों, चाहे फिर वे पक्षी हों या प्राणी, सभी के प्रति सौहार्द भाव रखना हमारी संस्कृति है। भारतवर्ष में सभी जीव-जन्तु एवं प्राणियों के साथ 125 करोड़ की आबादी रहती है और उसमें यदि किसी के प्रति अन्याय होता है या किसी को कोई छोटा सा घाव भी लगता है, तो हमारे देश के लोग उसे अपना समझ कर सभी के दुख को अपना दुख समझते हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया**) *पीठासीन हुए]*

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, समाज के उस वर्ग के साथ अभी तक जो व्यवहार हुआ और उनके संदर्भ में जो यहां दिखाया गया, उसके संबंध में तमिलनाडु गवर्नमेंट और अन्य सरकारों ने जो एक्शन लिया और इनीशिएटिव लिया, उसकी मैं सराहना करता हूं और उनके लिए ऐसा होना चाहिए। इसमें जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। उन्हें तो ईश्वर ने ऐसा बनाया है। कुदरत ने उनके साथ अन्याय किया है। कुदरत ने जो अन्याय किया है, क्या हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं? अगर कोई विकलांग है, उसके साथ कुदरत ने अन्याय किया है, तो उनके लिए हमने कानून बनाया है। कानून के तहत उनको हमने कुछ सुरक्षा दी है। वैसे ही समाज का एक वर्ग यह भी है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे न्याय दिला सकते हैं - राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग समाज के दूसरे लोगों की तरह जी सकें, सारा समाज उनके साथ अपनेपन का व्यवहार करे, कानून की दृष्टि से उनको सभी के बराबर मान्यता मिले। अगर हम उन्हें विशेष मान्यता दिलाएंगे, तो आज तक सोसायटी में उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दूर करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। वे कितने समय तक इसे सहन करेंगे? ट्रांसजेंडर लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं या बस स्टेशन पर जाते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई लग्न या त्यौहार हो, वे टोली के रूप में आते हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि चले जाओ। वे बाहर खड़े रहते हैं और लोग उनको आने के लिए मना करते हैं, ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको हम अछूत समझते हैं। उनको अछूत समझने की वजह से सोसायटी में सभी के बराबर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अभी तक उनके साथ जो हुआ, सो हुआ, लेकिन क्या नई सुबह नहीं हो सकती? क्या हम नई स्थिति पैदा नहीं कर सकते? क्या हम उनको ऐसे अवसर प्रदान नहीं कर सकते, जिससे कि अभी तक उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, उसको सकारात्मक दृष्टि से बदला जा सके? मुझे लगता है कि हमें उनके लिए... मेरी तो सरकार से विनती है कि क्यों नहीं सरकार ही उनके लिए कानून लेकर आए, जिससे कि इस वग के साथ, ट्रांसजेंडर लोगों के साथ अच्छी तरह से न्याय हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि उनके लिए कानून बनाओ, उनके साथ समाज में बराबरी का व्यवहार हो, ऐसा कानून

[श्री मनसुख एल. मांडविया]

बनाकर उनको न्याय दिलाओ और मुझे लगता है कि जिन्होंने यह किया है, जिस स्टेट ने ऐसा किया है, बहुत अच्छा किया है। यहां तमिलनाडु के हमारे सहयोगी साथी एम.पी. बोल रहे थे, तमिलनाडु में उनके लिए जो व्यवस्था हुई है - उनके लिए पेंशन की योजना हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, उनके self help groups बनाए गए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। क्या सारे देश के लोग ऐसा नहीं कर सकते, जिससे कि उनकी आमदनी हो, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए? गवर्नमेंट की सुरक्षा की दृष्टि से वे स्वमान में जी सकें, उनकी स्वमान की राय हो सके? जब उनकी स्वमान की राय हो सकेगी तो उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी बस स्टेशन पर, किसी लग्न प्रसंग में या किसी और प्रसंग में कभी भी किसी के सामने अपना पेट भरने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि इस समुदाय को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कानून में ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे कि वे self sufficient हो जाएं, उन्हें अपने रोज़गार के अवसर मिल सकें और उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तभी वे सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है और सारे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है कि समाज में वे उन्नत मस्तक से जी सकें, समाज में उनके साथ समान व्यवहार हो, समाज उनकी जाति और उनके पिछड़ेपन को न देखे। ऐसा कानून बनाकर हम उनको प्रोटेक्ट करें। माननीय उपसभाध्यक्ष जी के माध्यम से मेरी सरकार से यह विनती है कि सरकार ऐसा बिल लाए जिससे कि उन्हें सामाजिक सिक्योरिटी मिल सके, धन्यवाद।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भाई तिरुची शिवा जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने समाज के एक ऐसे तबके के दर्द का एहसास किया, जो दूसरों की खुशी में खुश होता है। मेरा मानना है कि मालिक कहता है कि तुम हमारी मखलूक पर रहम करो, हम तुम पर रहम करेंगे। मखलूक, चरिन्द, परिन्द इंसान और जानवर, सब होते हैं। अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार का जो विज़न डाक्युमेंट आया था, उसमें 'समग्र विकास' की बात कही गयी थी, 'सर्वजन हिताय' की बात कही गयी थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह समाज का वह तबका है, जो दूसरे के घर बच्चा पैदा होते देखकर खुश होता है और इतना खुश होता है कि खुशी में नाचने लगता है। यह समाज का वह तबका है, जिसको विपरीतलिंगी लकब दिया गया है, उपाधि दी गयी है। इसने खुद अपने आपको विपरीतलिंगी नहीं बनाया है, बल्कि कुदरत ने उसको यह इनाम दिया है, कुदरत ने उसे विपरीतलिंगी बनाया है। लेकिन हिन्दुस्तान की आज़ादी के 67 बरस बीत जाने के बाद भी अगर समग्र विकास की परिधि में वे विपरीतलिंगी लोग नहीं आते, जो दूसरे की खुशी में खुश होते हैं – खुद उनके घर बच्चा नहीं होता, लेकिन दूसरे के घर बच्चा पैदा होते देखकर खुश होते हैं – तो यह दुर्भाग्य है। मैं एक बार फिर भाई शिवा को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने समाज के उस तबके के दर्द को छूने की कोशिश की है, जो हिन्दुस्तान के इतिहास में एक बड़ा स्थान रखता है और बड़े-बड़े योद्धाओं को उनका सहारा लेना पड़ा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बहुत सारी बातें कही गयी हैं, विधेयक बड़ा मुकम्मल है। विधेयक में उन्हें आर्थिक और सामाजिक संरक्षण की बहुत सारी बातें कही गयी हैं, लेकिन मैं और आगे जाकर कहता हूं - इस विधेयक में जितनी बातें कही गयी हैं - मैं कहता हूं कि उन्हें राजनैतिक संरक्षण भी दिया जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से राज्य सभा में आता हूं। उत्तर प्रदेश को यह गर्व प्राप्त है कि वहां से एक विपरीतलिंगी व्यक्ति विधान सभा में आ चुका है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मध्य प्रदेश को भी यह गर्व हासिल है कि मध्य प्रदेश की विधान सभा में भी आवाम ने एक विपरीतलिंगी व्यक्ति को विधायक बनाया था लिहाज़ा इस बिल को अगर मुकम्मल करना है और उन्हें पूरा इंसाफ

दिलाना है, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सामाजिक-आर्थिक संरक्षण के साथ-साथ उनको राजनैतिक संरक्षण भी मिलना चाहिए। जब राजनैतिक संरक्षण मिलेगा तो उनके साथ होने वाली नाइंसाफी नहीं होगी। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आगरा स्टेशन पर बैठा हुआ था। एक विपरीतलिंगी व्यक्ति यह सोच रहा था कि वह मर्दाने बाथरूम में, युरिनल में जाए या लेडीज़ युरिनल में जाए। जब वह लेडीज़ वाले में दाखिल हुआ तो लेडीज़ ने उसे डांटा और यह कहा कि तुम यहां कैसे आए? मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। इस प्रकार समाज का यह तिरस्कार, जो वे झेल रहे हैं, वह तिरस्कार उनकी अपनी गलती से नहीं है, बल्कि कुदरत ने उन्हें दिया है। उन्हें संरक्षण देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए, उनको इंसाफ देने के लिए यह आवश्यक है कि 'समग्र विकास' का नारा देने वाली, 'सर्वजन हिताय' का नारा देने वाली सरकार उनको न्याय दे, उनको आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक संरक्षण प्रदान करे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

†**چودھری منوّر سلیم (اترپردیش) :** اپ سبھا ادھیکش مہودے، سب سے پہلے میں بھائی تروچی شیوا جی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سماج کے ایک ایسے طبقے کے درد کا احساس کیا، جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ تم ہماری مخلوق پر رحم کرو، ہم تم پر رحم کریں گے۔ مخلوق، چرند، پرند، انسان اور جانور سب ہوتے ہیں۔ ابھی راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں سرکار کا جو ویژن ڈاکیومینٹ آیا تھا، اس میں 'سمگر وکاس' کی بات کہی گئی تھی، 'سروجن ہتائے' کی بات کہی گئی تھی۔

اپ سبھا ادھیکش مہودے، یہ سماج کا وہ طبقہ ہے، جو دوسرے کے گھر بچہ پیدا ہوتے دیکھ کرخوش ہوتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں ناچنے لگتا ہے۔ یہ سماج کا وہ طبقہ ہے، جس کو وہرت-لنگ لقب دیا گیا ہے، اپادھی دی گئی ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو وہرت-لنگ نہیں بنایا ہے، بلکہ قدرت نے اس کو یہ انعام دیا ہے، قدرت نے اسے وہرت-لنگ بنایا ہے۔ لیکن ہندوستان کی آزادی کے 67 برس گزر جانے کے بعد بھی اگر سمگر وکاس کی پریدھی میں وہ وہرت-لنگ لوگ نہیں آتے، جو دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں - خود ان کے گھر بچہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کے گھر بچہ پیدا ہوتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ میں ایک باد پھر بھائی شیوا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سماج کے اس طبقے کے درد کو چھونے کی کوشش کی ہے، جو ہندوستان کے اتہاس میں ایک بڑا استھان رکھتا ہے اور بڑے بڑے یودھاؤں کو ان کا سہارا لینا پڑا ہے۔

†Transliteration in Urdu Script.

[चौधरी मुनव्वर सलीम]

اپ سبھا ادھیکش مہودے، اس ودھیک میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ ودھیک بڑا مکمل ہے۔ ودھیک نے انہیں آرتھک اور سماجک سنرکشن کی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن میں اور آگے جاکر کہتا ہوں ، اس ودھیک میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انہیں راجنیتک سنرکشن بھی دیا جانا چاہئے۔ میں اتّر پردیش سے راجیہ سبھا میں آتا ہوں۔ اتّرپردیش کو یہ گرو حاصل ہے کہ وہاں سے ایک ویپرت-لنگ شخص ودھان سبھا میں آ چکا ہے۔ میں مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہوں۔ مدھیہ پردیش کو بھی یہ گرو حاصل ہے کہ مدھیہ پردیش کی ودھان سبھا میں بھی عوام نے ایک ویپرت-لنگ شخص کو ودھایک بنایا تھا۔ لہذا اس بل کو اگر مکمل کرنا ہے اور انہیں پورا انصاف دلانا ہے، مانئے سماجک اور ادھیکارکتا منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے انورودھ کرتا ہوں کہ سماجک-آرتھک سنرکشن کے ساتھ ساتھ ان کو راجنیتک سنرکشن بھی ملنا چاہئے۔ جب راجنیتک سنرکشن ملے گا تو ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی نہیں ہوگی۔ سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں آگرہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ویپرت-لنگ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ وہ مردانہ باتھ روم میں، یورینل میں جائے یا لیڈیز یورینل میں جائے۔ جب وہ لیڈیز والے میں داخل ہوا تو لیڈیز نے اسے ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ میں خود اس کا گواہ ہوں۔ اس طرح سماج کا یہ ترسکار، جو وہ جھیل رہے ہیں، وہ ترسکار ان کی اپنی غلطی سے نہیں ہے، بلکہ قدرت نے انہیں دیا ہے۔ انہیں سنرکشن دینے کے لئے، ان کو نیائے دینے کے لئے، ان کو انصاف دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ 'سمگر وکاس' کا نعرہ دینے والی، 'سروجن ہتائے' کا نعرہ دینے والی سرکار ان کو نیائے دے، ان کو آرتھک، راجنیتک اور سماجک سنرکشن پردان کرے۔ بہت بہت شکریہ۔

(ختم شد)

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I would like to compliment my brother Member, Shri Tiruchi Siva, for bringing in this Bill in the way he has done it and the matter that he has brought in. Sir, in a polite society, we do not mention the word 'hijra' or whatever we call it. It is an unspeakable word. The people who belong to this community are considered totally untouchable. The way Mr. Siva has brought it out has, at least, touched our conscience that we are discriminating against our own brothers and sisters, a creation of God, for which they are not responsible. Therefore, Sir, I would urge, very simply, through you, upon the Central Government that let them bring out a law on the subject giving some leeway to the States to make such little amendments as they like to cover the whole gamut of the activities of these unfortunate people. Sir, before I conclude, I would like to quote a famous judgement delivered by the Bench of Justices K.S. Radhakrishnan and A.K. Sikri. Sir, with your permission, I am quoting a portion of the judgement. It says, "Seldom, our society realises or cares to realise the trauma, agony and pain which the members of the transgender community undergo. It does not appreciate their innate feelings, especially of those whose mind and body disowned their biological sex. Our society often ridicules and abuses the transgender community. They

are treated as untouchables forgetting the fact that the moral failure lies in the society's unwillingness to contain or embrace different gender identities and expressions, a mindset which we have to change."

Sir, this is our attitude towards the transgenders. I will only appeal to you that the Central Government should take note of this fact that they require protection and support of the entire country because they are as much Indian citizens as any one of us, and, they are entitled to as much protection of law as any one of us have it. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri M.P. Achuthan.

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, I fully support this Bill and congratulate my dear friend, Mr. Tiruchi Siva, for bringing such a comprehensive Bill. Many of the main issues have been dealt with by other speakers.

We, as a society, consider transgenders as outcast. The attitude of the society has to be changed. If you see it number-wise, it is a small population, and, therefore, cannot influence the electoral results. Therefore, the political parties normally do not consider them as a vote bank. My request is that the issues of the transgenders must become an integral part of the agenda of the political parties in India. Sir, in the last 68 years, we, as a society, did not consider the issues of these people. It is time to do this because after the verdict of the Supreme Court, this issue is in public domain. Now, it is up to the Government to take action and give it a legal framework, and, this Bill, which is a comprehensive Bill, must be the basis for the same.

I appeal to the Government that on the basis of what Mr. Tiruchi Siva has drafted, it should bring a Bill in the next Session of Parliament itself so that justice can be done. It is basically a human rights issue, it is a democratic issue. If we consider it in that way, we will be doing justice to ourselves as a society. So, I again request the Government to come out with a comprehensive legislation on this issue. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shrimati Vandana Chavan; not present. Ms. Anu Aga.

MS. ANU AGA (Nominated): Sir, I am aware that many things have already been said but, I think, it is worth repeating. In our society, we deny the existence of transgenders and also there is discrimination and taboo against them. As a result, we do not even know

[Ms. Anu Aga]

the exact number of transgenders existing in India. For no fault of theirs, their families in which they are born are ashamed, and, conceal their identity from the society and shun them to places where hijra population lives.'Hijra' is considered a derogatory word and yet we have not found a respectable substitute word for it. Deprived of formal education and skill, they are forced into traditional occupations like blessing a newly-born or a newly-married couple or become sex workers or beggars. Society and Government so far accepts only the male and the female genders and hence transgenders are forced to identify themselves either as male or female. Some instances were given. For example, as a woman, she enters a woman's railway compartment and she has to deal with smirks and stares. The first requirement is their existence has to be given a legal recognition. Instead of listing them as others, we need to have male, female and transgender in all the forms that we have to fill. In schools, we need to openly talk about transgenders so that our children are sensitized and learn to accept them as normal human beings. Because of this ignorance and bias, there is humiliation and social ostracism, and most transgender students give up studies. These children require counselling and support. There are many legal and special protections transgenders need. But as a first step, if we, the Members of Parliament, recognize and respect their existence, many other benefits are bound to follow. Thank you.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana) : Respected Vice-Chairman, to begin with, I salute my elder from Dravidian culture, Shri Tiruchi Siva, for framing and making this document as the property of the Indian Parliament, of Indian Government and also of Indian people. Shri Tiruchi Siva has drafted this Rights of Transgender Persons Bill with ten Chapters, 58 Clauses, including all the aspects that are required for a comprehensive law. This shall go into the history of Indian Parliament. We shall not forget the Paramatma Tattva. These transgenders are from all the cultures and religions. But to make a mention, I take the Vaishnavite formula. Shri Maha Vishnu himself claimed:

''न स्त्री न पुरुषः न षंडा

विश्वमयं तु विश्वविभुव तु''

He is also claimed to be mohini, neither man nor woman. And, as rightly recollected by Tripathiji, the Mahabharata establishes the role of not only Brihannala for the transient

period of their crisis in the Virata Parva but also reflects the complication of to-be framed society in the shape of Shikhandi before Bhisham Pitamah. Now, the status and the plight of transgender persons is more pathetic than Shikhandi. The word 'hijra' is an Urdu-Hindustani word. It is having its root from Arabic 'hijr' meaning the person who is moving away from his milieu. The person who is going away from his tribe. That is how it has come. Now, it is being treated across several nations as if it is a community. No; it can never be a community. They belong to several castes, creeds and religions. But that is the bio-technological complication of life. There are transgenic animals, there are transgenic plants and likewise, the transgender lies in human beings. Just sympathy and empathy towards them will not serve at all. Recognition and respect, as advocated by Anu Agaji, will alone elevate our level of standard as human beings, that too within our country, India. I also salute the Mayor of Raigarh in Chhattisgarh – the first transgender Mayor Madhu Bai Kinnar. Her election got the attention and attraction of the global media. That transgender person, Madhu Bai Kinner, has defeated the candidate of the present ruling Party, not only at the Centre, but also in Chhattisgarh. I salute the capacity and stamina of the community, which is not to be. In America, in a State called Utah, just twenty four hours earlier, the Utah Legislature has adopted a legislation providing sufficient rights to lesbian, gay, bisexual and transgender persons. Across the nations, the LGBT community is a challenge and, equally, attracting the attention and the respect. This is high time for us to get ready to accord the due respect and provide sufficient remedies, amenities and facilities and the separately required, specially required welfare to that complication. At this juncture, I will not only appeal to the Union Government to come out with a comprehensive support mechanism with proper institutional support and safeguards but I also call upon the scientific community that there is a facility for a male person to become female, a female to become male. When it is happening, why this trauma to a transgender person? Let the scientific community rise to the occasion and evolve the required bio-technological scientific innovations so that they can come out of their trauma. Their trauma is not only societal, but they undergo a very severe psychological trauma. Hence, there is every necessity to evolve a certain support mechanism to the research institutes, which are having concentration on the DNA and other formulations, to focus on these aspects also.

It is mentioned by Mr. Siva in his comprehensive document. Since this happens to be a Private Member's Bill, we all know that it is not going to become a law.

SHRI TIRUCHI SIVA: Why not?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: It will become a law only when the Union Government of the day adopts it and moves it as its own Bill. Only then is there scope to make it a law. For that, let the Union Social Justice and Empowerment Ministry come up with its mechanism to first evolve the immediate requisites of the institutions such as grievance redressal cells to begin with and subsequently, as proposed by Mr. Siva in his nice piece of legislation, the requisite welfare mechanism and protection to them on a par with the SC and ST Act. This will bring respect to their lives and ease the trauma.

With this appeal, I once again appreciate the gesture, care and concern of Mr. Tiruchi Siva. It is high time the Union Government responded to the present demands and needs of the transgender population. Thank you very much, Sir.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, the very fact that almost all the people are supporting a Bill like this should not require repetition at all, merits adoption.

At the very outset, I would like to congratulate my best friend Siva on working out the entire Bill in detail. I was just thinking that it is some kind of support that we should give to the people who have been discriminated against for no reason and fault of theirs' at all.

Sir, birth is natural. It is not legal. When a child is born, there is nothing like human rights. I think first he inherits his natural right and later on you bring human rights. He asked whether the word 'hijra' is parliamentary or not. They are known by many names. We call them jogtas, kothi, shivshakti, etc. Many names are given to them. But the reality tells you that they do exist and they are part of society. My best friend talked about their diverse presence in the present milieu and present society.

Having realised the reality, which you cannot shun. As Mr. Gill said, somehow we have some kind of aversion or some kind of distaste or attitude towards them. Why is it so? All of us have seen Mr. Siva's Bill in detail. All of us are talking about certain facilities and rights to them. According to me, if you read the Constitution, you will find that the rights do exist for them. They are not being given is another matter. The International Convention No. 62 is there. The Constitution of India gives me the right to identity, life style, practices, etc. All these things are there. Justice Radhakrishnan and Justice Sikri of the Supreme Court have said that they should get the full rights. But, unfortunately, the present Government, Mr. Minister, Sir, has challenged the Supreme Court Order. Later the Attorney General said, "No, no, we have not challenged it. We wanted a clarification." No need for clarification. They exist. It is his plight. It is gory

plight. What we must do is that we must react. We must respond. He says the first such mayor is Madhu Bai Kinnar. It is not only Madhu Bai Kinnar. Earlier we had another mayor in Madhya Pradesh. Today, we have two or three MLAs. They are there. But they are not getting it as a right, as part of social system. That is what Siva's concern is and that is what the concern of all of us is. We exist along with them but unfortunately think that some kind of sympathy should flow from us towards that section.

Sir, I don't want to repeat all these things. Many things have been said. Mr. Tripathi had brought in all the statistics here. These are available. But, let me tell you that it is not only about Ruma Nagaraj who spoke about them. Many things are said which are sometimes not good. Time and again, we have been saying that statistics about transgenders are not adequate and are not at all correct. Ruma might have said much more. Nagrajan might have said that. Earlier, the novels of Tamil Nadu writers, Vadlamani and Revathi, were translated all over the world in many languages. Mr. Tripathi referred to Garuda Purana. It has given it in detail. Scriptures back our claim; international laws back it; Constitution backs it; our own views back it. Yet, this kind of a paradoxical situation exists. We must say that somewhere it should have stopped.

Sir, through you, I would say that Mr. Siva has given what exactly is required. Constitutional rights are given. But, basically, let us understand why this mental antipathy has come. Why is this reservation in us? It could be their behavioural pattern; it could be their body language; it could be our own innate feeling towards something which is not you. We are trying to tolerate the outcastes. So, what is required is, as he said, genetic studies, genome studies, etc. Presentations tell you that there can be correctional methods. It is not that the reassignment surgeries are going to correct it. A man can be what he is. A lady can be what she is. A transgender can be what he is. But, if there are different behavioural patterns, then there are psychological studies and trends which can be factored in. I request the Government to look into this. Let us have this kind of motivational courses which correct body behaviour and our own attitude towards the other man. This is the basic thing.

Sir, as a Minister, I have experienced it myself when people were not allowing transgenders getting admission in schools. First, we thought that we would have separate seats for them. Then, we had separate classes, motivational classes, for them. So, this kind of a thing must be tried. I have seen the Bill. I think, the mover of the Bill, Mr. Siva, must also look into that particular issue. He has mentioned only about physical correction, reassignment and medical needs. All these things are there. The Minister has

[Dr. K. Keshava Rao]

seen these things. I don't want to repeat them. First of all, let us all help them come out of their trauma. Let us all go with positive responsiveness and own them as part of this society. First, it must come in us as to what exactly can be done through law or social awareness. That is the first thing we must do. Secondly, there should be some kind of motivational classes for them where they accept us as equals instead of saying that they are not part of us or are not equals to us. That should come in us and them. Then comes the things which Mr. Siva has given in the Bill like educational reservation, separate treatment in hospitals, etc. All these things are there. So, I don't want to repeat them. The Bill is very comprehensive. He has comprehended the problem and brought in all those things in a comprehensive fashion.

Sir, I have two or three things to say. There was an expert committee which had looked into it. I know it. I also congratulate the State of Tamil Nadu. Mr. Ramaswamy Naicker, in one of his writings, wrote about this gender and how it should be brought in and made a part of the society. So, I congratulate the Tamil Nadu Government. I think the hon. Member from Tamil Nadu was talking about things like pension. This is we should do. It is not that we are giving ₹1,000. But It is only saying that we own you. We are part of you. West Bengal has also started a Welfare Board. We have not heard much except that they have prepared an action plan. They are looking at the welfare aspect of it like amenities, hospitals, etc. First, make them a part of the milieu. That kind of awareness must come in them. We need some kind of studies which focus on the correctional methods, behavioural patterns, etc. Then comes the physical thing. Sir, the worst discriminated ones are two, as Mr. Tripathi has rightly said. One is kothis whom you call hijras or shivashakti. Number two is physically and mentally challenged. These two exist. Let us not show misplaced sympathy at all. But let us own them. It is not our owning them. Let the society own them. Let the society look to you and them equally. I think that is the sprit of this Bill. Since all of us have lent support to the Bill the Minister should accept it as his Bill. As my friend, Mr. Bhaskar has said, this Bill has come from a private Member, so, it can't become an Act.

SHRI TIRUCHI SIVA: In the past Private Member's Bill had been passed and had become an Act.

DR. K. KESHAVA RAO: Rather I would go that route. Let the Minister know that all the people here are agreeing with every part of what has been said in the Bill. Please bring it in the next session.

Lastly, as far as the NDA Government is concerned, you have replied to the Supreme Court. You are unnecessarily mixing it with Section 377. Section 377 is unnatural practice and must be shunned. Transgender is by nature and one is born that way. Let me live, let me correct and let me lead as I want it, when you can't change. Section 377 of the IPC is regarding gays or homo sex. It is to practice unnatural sex. Mixing these two in seeking the Supreme Court clarification when you have argued has created all these problems.

I have discussed the issue with the Mover of the Bill, Mr. Tiruchi Siva. He did not mix up those two issues at all. He has talked about a particular sect which Mr. Bhaskar has very well explained. It is not only Vishwapuranas or Sanskrit scriptures which have elaborated. Due to bio-genetic formations these things happen. Let them get all the rights. Let them be part of the society to which they belong. They are part of our society. I congratulate this Government also. We have elected them as MLAs and Mayors. They are asserting themselves. They have their Kalyana Sangams which is fighting for them. We are also fighting for them. We are talking for them in this way, in this fashion, so loudly to show that we all agree with that kind of movement. Let us give them a constitutional right because by birth they have got that natural right. You need not give them through your Acts or human rights laws. But in what manner you would like to integrate them with the present society which is totally prone to discrimination with each other, a caste ridden society is important. Let not this become a part of the caste. Let this become part of the humanism. On behalf of all, and on my own behalf, I request the Minister -- since all of us are agreeing to it -- look into it, as it is you who can accept it. I would like to insist that this Bill should be passed. Otherwise, please give an assurance that an expert committee would be constituted, which will study it, the base being the present Bill. If we are also coming out with something, wherein they have all the rights given, and making them a part of the society, without our saying as if we have not done anything, and for them to say that they have a right, they are part of the society and part of the constitution, that will be good and is what we are seeking. And I hope the Government will look into this. Thank you.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you. I support this Bill moved by our hon. Member, Shri Tiruchi Siva, for the protection of the rights of the transgender persons which is a well structured Bill. As other Members have said, the job of the Government to draft the Bill has already been done by Mr. Siva. I feel that the hon. Minister is also a very nice gentleman. We know it. He has to take it as a historical event to accept this Bill as the Government Bill. If you

[Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan]

feel that you cannot accept it mmediately, at least, you should give an assurance that it would be taken up in the second part of the Budget Session as a Government Bill. Why we are stressing on this particular point is that many of the Members of Parliament are working and doing a lot of research to come forward with a piece of legislation. We are not following the model of the United States' Parliament where Parliament Members were bringing a lot of Bills which were accepted according to the Constitution. Members' names are also mentioned saying that the Bill was moved by so and so, and the President of United States accepts them. In certain cases only, if it is not favourable to their own strategy, then, they may not accept it. Otherwise, these Bills are also made as one of the Bills which are binding upon the Government. Therefore, this structure was also taken into consideration when our Constitution was drafted. And this part of the hour, two-and-a-half hours, allotted for Private Members is a special thing for bringing in Members' contributions. Whether they are sitting in the Opposition or in the Ruling Benches, their own individual recognition is brought up by this method of Private Members' Resolutions or Private Members' Bills. But this particular Bill is on the basis of an International Convention. Many international organizations have come forward and said that every domestic law should have this protection to transgenders. We were having it as a conventional method. You know very well that even in the Mughals' period and subsequent periods, these people were used for the protection of Princess and ladies of the Kingdom because they were very bold, very sincere and very loyal to the Kingdom. Therefore, they were protecting the lady folks of the Kingdom. Subsequently, they were treated excellently in their own identity. But after a certain point of time, they became one of the stigmas of the society. They started to feel that they were being neglected. They were ridiculed by others. They wanted to show their identity by using a different type of dress, using their body behaviour, using their tones for certain purposes. And further they started to be abused by the society. That is why the Parliamentary Forum on Human Rights and also the Parliamentary Forum on HIV AIDS have taken up this issue and the United Nations Development Organisation is also taking up a special case study. I could attend that Conference at Bangkok in 2010, where the Asian people are very much affected by this transgender stigma. The European countries could come forward with a protection provision on the basis of the European Constitution, and the European Courts are also protecting them. They have got equal rights everywhere. They are identified as a third gender. They are having their own dignity. They are also protected health-wise. Their surgery method, that is, the procedure, is also accepted by the European countries.

4.00 P.M.

The United States of America is also accepting them. Canada is also accepting them. Also, Argentina and many others in the South American countries are accepting them. Even some of the Asean countries are, gradually, coming up with legislations. And we want to create awareness among the people that this is not the sin of anybody. Our friends were citing many of the Vedic happenings. Shikhandi is one of the characters who was holding a small Kingdom and who was woman in her earlier birth. When she could not get married with a prince, she went to Bhishma. But Bhishma refused and the story went on like that. The story further goes on that Shikhandi hid behind Arjuna and killed Bhishma.

That is the story which we have studied. This shows that the third gender is accepted as the chief of the kingdom. This is the story which talks about bravery of third gender. Similarly, they have got every capacity to do something in the world. Therefore, we have to treat them as human beings, whether they are working for the development of the society or whether they have to be brought into the mainstream as part of the human activities or whether we are giving equal justice in each and every aspect. Now we are citing very boldly the incident of winning of the first Mayor named Madhu Bai Kinnar. She was dancing and singing in the train but, finally people accepted her as the Mayor of a city. These are historical incidents happening in India and the judgment which was pronounced by the Supreme Court has to be taken into consideration by the hon. Minister and the Government. The judgment is having 113 pages. Justice Radhakrishnan has given a clear judgment. I will just read one paragraph alone. He has cited all the incidents of what is happening throughout the world in this particular issue and he finally comes to the conclusion that you have to come forward with legislation. It is a two-judge Bench judgment. They gave concurrent judgments and said that domestic legislations should also come forward to protect these people. I will just read how they look at the issue of transgender under Article 14. I will quote paragraph 54. "Article 14 of the Constitution of India states that, The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Equality includes full and equal enjoyment of all rights and freedom. Right to equality has been declared as the basic feature of the Constitution, treatment of equals as unequals or unequals as equals will be violative of the basic structure of the Constitution." In that way, it has got a lot of justification. And, finally, the judgment says that the State has got certain obligations to come forward with legislation. This work is done by our hon. Member, Shri Siva,

[Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan]

here. Beyond all political things, I have to say that in many of the social aspects, Tamil Nadu is the pioneer, and more so, we feel that the present Government and also the earlier Government from 2006 itself, Dr. Kalaignar as Chief Minister has recognized this particular gender as the third gender. In Tamil, they call it as Thirunangai. That was the word coined by him and they were given all the facilities and a Board was also constituted. I hope this was the inspiration on which Shri Siva has brought this Bill also and subsequently the present Government is giving a lot of incentives for this purpose. One of our friends was citing the word, 'gay'. We should not confuse ourselves with transgender and gay. Transgender is a recognition of a particular type of people who have not committed any sin, who have not committed any violation of the civilized system. It is only a change in the anatomy. When they were born, they were having certain type of anatomy. That is the only thing. They could not procreate. They cannot bring forth children. They cannot be the cause of bringing children. That is the only difference. But there are many other incidents also happening that by proper surgery, procedurally they can also bring forth children. Science is motivated now. Therefore, we feel that gay is totally a new method of having single sex, to live together. We cannot fully accept it. There may be a controversy in that discussion. I feel that we should not mix both the things. This is purely a matter which civilization has accepted as a third gender. But, in the 19th and 20th Centuries we neglected that cultural aspect. We, the Indians, have protected the third gender. Now, we have to rehabilitate them. How to rehabilitate them? How to protect their rights? How to bring them into the mainstream? How to make them potential persons for the development of society and nation? How they should sit besides us, equally, without any mockery or stigma are the issues which are important and the Bill has drafted keeping all these things in mind. I feel this Bill will give them life by way of statutory support. It is not grace that we giving them. It is not that we are doing any charity, but all we are doing is recognizing a right which is given to them for centuries by our Indian society, our Indian civilization which has to be protected by way of domestic law.

Thank you very much.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Thank you Vice-Chairman, Sir. I must congratulate Tiruchi Siva for introducing this Bill. It has a very inclusive definition of transgender persons, covers a broad spectrum and has an excellent definition of discrimination which includes provisions for reasonable accommodation.

Sir, many of the speakers who have spoken before me have already talked about how ancient Indian culture has always been very inclusive when it comes to accommodating and understanding the needs and rights of transgenders. We have talked about Shikandi, we have talked about Brihannala and we have also talked about Mohini. Sir, my own House God is Belur Channakeshava, who is Lord Krishna dressed in woman's clothes. So, there is always been a certain tolerance and willingness to be inclusive in our ancient culture. That spirit must be incorporated in the way we run our country today. Sir, that has not necessarily happened historically in the last few decades or even today and we must do much more.

Here, I would like to point out that the Government of India has to respond to a historic judgment of the Supreme Court in the National Legal Services Authority Case. In this context, the Government has only filed a clarification petition. This is delaying the resolution of this legal process. That way, it does not provide for speedy justice to this vulnerable, stigmatized minority.

Sir, while Tiruchi Siva has done an extraordinary job in drafting this Bill, I do think that it needs certain changes to bring it in compliance with the principles enunciated in the NALSA judgment, in the Report of the Ministry of Social Justice and Empowerment's Expert Committee on issues relating to transgender persons and also the Verma Committee Report on amendments to the Criminal Law relating to sexual violence.

Let me just enumerate these as quickly as I can. First is recognition of legal identity. The guiding principle of NALSA judgment is legal recognition of gender identity -- male, female or third gender -- based on self-identification amongst people. For this, there is a legal procedure that has been proposed which includes a report which involves the District Screening Committee and a Self-declared Affidavit.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

Sir, I recommend that this Bill should provide a separate section to affirmatively recognize the right to legal recognition along with providing procedure for the same.

Sir, Tiruchi Sivaji has used the term 'transgender children.' Sir, I feel, it is a tricky term, because children, until they become adolescents, are not necessarily fully aware of their identity and, therefore, it is better to use a term that could be called 'gender non-conforming children', along with the term 'transgender children.' And, I recommend that children should be brought under the purview of this Bill who are not only seen to

[Prof. M.V. Rajeev Gowda]

be non-conforming but are also perceived to be individuals who are non-conforming by others. This is a very tricky matter. So, I would suggest that the Bill include the term 'transgender children', 'gender non-conforming children' or 'children perceived to be transgender'. It seems a little complicated. But, that is more appropriate for children. I would also urge Shri Tiruchi Siva to expand the education chapter to provide for inclusive education and adult education programmes. He already has done that. But the basic challenge faced by transgender children is harassment, discrimination and bullying. That is something we need to change by sensiting teachers, by sensiting students. Already, we have laws against ragging. For this group, we should not only have the establishment of anti-ragging, anti-bullying, anti-harassment cells and anti-discrimination cells, but this should also be sensitized in education right from early childhood to later years, and should also be sensitized and incorporated in teachers' training as well.

Sir, I have one disagreement with the Bill. Sivaji suggests that we should have a separate, exclusive transgender rights court. I think, it is more important for the mainstream legal system to be sensitive, to incorporate matters associated with transgender persons and to deal with in the same manner as anybody else would be dealt with. So, in that existing framework...

AN HON. MEMBER: He has put that.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Has he put that? Very good then.

In terms of freedom of speech and expression of transgender community, this is again an interesting issue. On the freedom of speech under Article 19, this Bill also recognizes the right for the transgender community. But there are certain crucial components that were elaborated in the Supreme Court's NALSA judgment. The Court read the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(A) to include the right to expression of one's self-identified gender. The self-identified gender can be expressed through dress, words, action or behavior or any other form. A transgender's personality, the Court notes, could be expressed by the individual's behavior and presentation. The State can't prohibit, restrict or interfere with the transgender's expression of such personality subject to restrictions into the purview of the law.. *(Time-bell rings)*

I need two more minutes, Sir. I am finishing, don't worry. It is an important issue. Sir, going beyond the Bill, there are two major issues. One is providing adequate protection against sexual violence. Under Section 375, we don't take into account sexual violence

against the transgender community. I recommend that Section 375 of the IPC be amended to make it gender neutral with respect to the victim as recommended by the Justice Verma Commission. This should ensure that even if the assaulter is male, the victim of any gender should fall under the purview of this Bill. Then, most importantly, Sir, we need to repeal Section 377 of the IPC. I think, the Minister of Social Justice and Empowerment could bring a path-breaking figure if he goes ahead and pushes for the repeal of this very, very regressive Section of the IPC. In the Naz Foundation judgment, we know that Section 377 continues to have a deleterious impact on the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender persons. This must be repealed as quickly as possible.

Sir, once that is done, we will see that Section 377 will not be used as a tool of abuse against transgender persons. If we can get rid of this particular clause, we will be doing justice to not just transgenders, but also to numerous people whose choice of sexual preference is different from the mainstream.

Sir, the Union of India has a grave constitutional responsibility in this regard. It is up to the current Government. As the Minister has seen today across party-lines, we have the support for this, this is an example of law that can be brought in because it has the support of everyone. Every one of us agrees that if we want to achieve the glorious goals of the Preamble of our Constitution, to ensure equality of status and opportunity, to ensure social justice, economic justice and political justice, we can't let the rights of transgenders be transgressed in any way. I urge upon the Minister to take forward the extraordinary work done by Shri Tiruchi Siva and to turn this Bill into an official Act. Thank you very much.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं श्री तिरुची शिवा के इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के समर्थन में बहुत ही सकारात्मक सुझाव रखे हैं, मैं उनके साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हुए, एक-दो महत्वपूर्ण बातें कह कर, समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। चूंकि बिल में विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की बात को उभारा गया है, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से इस समुदाय को लोग 'हिजड़े' या 'किन्नर' के नाम से पुकारते हैं, तो मैं उसी नाम का सम्बोधन करूंगा, ताकि वे लोग समझ सकें कि किसकी बात कौन कर रहा है? हमारे देश की बहुत सारी अच्छाइयां ऐसी हैं, जिनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश की डेमोक्रेसी को, हमारे देश में रहने वाले तमाम धर्म-मज़हब के लोगों की एकता को, यूनिटी को, दुनिया के लोग भारत की व्यवस्था को, भारत की सभ्यता को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश की एक विशेष काबिलियत के रूप में इसे दुनिया के अंदर देखा जाता है, लेकिन भारतीय समाज के ताने-बाने पर जब कभी गंभीरता से चिंतन-मनन करने का अवसर मिलता है तो बहुत सारी कमियां ऐसी निकल

[श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप]

आती हैं, जिनको देखकर कई बार तकलीफ भी होती है और दुख भी होता है। हमारा देश एक है, समाज एक है, हम सब लोग एक हैं, लेकिन एक समूह, एक वर्ग जो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसके परिवार के लोग अगर यह समझें कि यह किन्नर है, यह हिजड़ा है, तो उसकी बिना बैंड-बाजे के घर से विदाई हो जाती है। बेटी को विदा करो तो बारात आएगी, बैंड बजेगा। बेटा पैदा हो जाए, तो भी तमाम खुशियां, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जिस घर में किन्नर या हिजड़ा पैदा हो जाए, तो उस घर के लोग ही उससे मुंह फेर लेते हैं कि समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे घर में कौन पैदा हुआ है?

उपसभापति महोदय, इस सामाजिक भेदभाव, सामाजिक असमानता, सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए श्री तिरुची शिवा ने एक कानून की शक्ल में एक प्राइवेट मेम्बर बिल के तौर पर इस सदन में अपनी बात उपस्थित की है, लेकिन भारत की संसद की कुछ इस तरह की परंपरा रही है कि प्राइवेट मेम्बर बिल को रस्म अदायगी का एक ज़रिया मानकर भाषण हो जाता है, मंत्री जी का जवाब आ जाता है, अनुरोध हो जाता है कि वापस ले लीजिए, हम विचार करेंगे और बात समाप्त हो जाती है।

उपसभापति महोदय, क्षमा करेंगे, मुझे बारह वर्ष उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् में बैठने का मौका मिला और उस परिषद् के सभापति जी के अधिकारों, उनके दायित्वों और उनके कर्तव्यों को जानने का मौका मिला। पीठ से बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं, सरकार चाहे या न चाहे, लेकिन कोई विधेयक, कोई कानून, कोई बात अगर समाज के हित में है, तो निर्णय करने का पूरा अधिकार पीठ के पास रहता है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, he wanted you to give the direction to the Government.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : उपसभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इस विधेयक पर हम रस्म अदायगी से आगे चलें। इस बिल को हम कानून की शक्ल दें। इस बिल को हम कानूनी बिल के रूप में स्वीकार करें ताकि हमारी संसद पर दुनिया का, लोगों का भरोसा बढ़े। यह कोई पहला ऐसा अवसर नहीं है, यह पहला ऐसा विषय नहीं है कि किसी समूह के साथ injustice हुआ है, किसी समूह के साथ भेदभाव हुआ है। महोदय, हमारे देश और देश के तमाम लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि देश को आज़ाद होने के पहले हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में इतनी खामियां थीं ...इतनी दिक्कतें थीं कि दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को सामाजिक ताने-बाने में साथ बैठकर चलने का अधिकार नहीं था, साथ बैठकर खाने का अधिकार नहीं था। अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी। एक दलित ने किसी के साथ बैठकर खाना खा लिया तो उसकी नाक काट दी गयी। उसकी नाक इसलिए काट दी गयी कि वह दलित था। भारतीय समाज में अगर ऐसी व्यवस्था कायम रहेगी तो सामाजिक ताना-बाना कहीं न कहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : पुलिस केस नहीं हुआ? I am asking whether a case was filed or not.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : मैं अपील करूंगा..(**व्यवधान**).. सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपसभापति जी पूछ रहे हैं कि पुलिस केस हुआ या नहीं हुआ।

श्री उपसभापति : पुलिस केस फाइल हुआ या नहीं? आपने कहा कि नाक काट दी गयी।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : सर, केस होने से समाज की प्रतिष्ठा वापस नहीं आ सकती है, समाज का सम्मान वापस नहीं आ सकता है। जो एक विज़न किसी वर्ग के खिलाफ बन जाता है, उस विज़न को खत्म करने के लिए सख्त कानून की जरूरत है...(**समय की घंटी**)... इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज में हिजड़ों और किन्नरों को भी बराबर सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हों। महोदय, आदरणीय मंत्री जी बहुत सूझवान हैं, बहुत दर्द और तकलीफ वाले उस समूह से हमदर्दी रखते हैं, जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। ...(**समय की घंटी**)... मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को सरकारी विधेयक के तौर पर स्वीकार करके सदन में इतिहास बनाएं कि यह संसद देश के किन्नर और हिजड़ों के लिए भी कानून बनाकर उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकती है। उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री उपसभापति : मेरा एक सुझाव है, you mentioned an incident here, आपने जो नैरेट किया, it is very serious. You should ensure that a case is registered, and strong action is taken against the person, who has cut the nose of a Dalit. He should get the punishment. That is what you said. His nose was cut for eating together. That is a very serious thing. If it happened in this country, then, you should take it up. It is not enough that you speak here.

SHRI NARENDRA KUMAR KASHYAP: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should go and enquire into it. If no action is taken, you should take it up very seriously. You can raise that incident even here. It is an atrocity on a *. It is an atrocity on a Schedule Caste.

SHRI AMBETH RAJAN: Sir, * is not the proper word.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know; I know. I withdraw that word. I agree, it should be Dalit. So, do that. Take it up. It is not enough that you mentioned it here.

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा) : सर, माननीय नरेन्द्र जी ने जो बात कही, वह इतिहास नहीं है। सर, 1972 तक पार्लियामेंट में 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल और रेज़ोल्युशंस पास हुए हैं, यहां पर 9 और लोक सभा में पांच। इतिहास बना हुआ है। 1972 के बाद से हॉल्ट हो गया जब प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्युशन को देखते हैं...(**व्यवधान**)...

*Withdrawn by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I said something else.

श्री भूपिंदर सिंह : रुक जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे फिर से एक इतिहास शुरू करा दें। आप इतिहास शुरू कराइए, उसमें हॉल्ट आ गया है। इसी हाउस में 1972 तक 9 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स पास हुए हैं।

श्री उपसभापति : श्री विशम्भर प्रसाद निषाद। निषाद जी, आप सिर्फ दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य तिरुची शिवा जी ने जो विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 को प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने इसमें अपने विचार रखे हैं, उनसे मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं। किन्नर या हिजड़ों के साथ प्रकृति द्वारा अन्याय हुआ है और उसके बाद उनके साथ समाज द्वारा अन्याय किया जाता है। शिक्षा से लेकर समाज में रहने का अधिकार उनको नहीं दिया जाता है, इसलिए यह बिल लाया गया है। यह बिल बहुत अच्छा बिल है। हम देखते हैं कि महिला किन्नर भी हैं, पुरुष किन्नर भी हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। कई माननीय सदस्यों ने यहां जिक्र किया कि अस्पतालों में पुरुष वार्ड और महिला वार्ड हैं। वहां पर यह समस्या आती है कि किस वार्ड में इन्हें रखा जाए। इसी तरह से शौचालय की बात आयी और जेल में भी दो ही वार्ड होते हैं - एक पुरुष वार्ड और एक महिला वार्ड। वहां पर उनको अलग से, तनहाई में रखा जाता है। यह समस्या है। महोदय, बताया गया कि उनकी संख्या 4.9 लाख है, निर्वाचन आयोग ने कहा 23,841 हैं। उपसभापति महोदय, शादी-विवाह और बच्चों के पैदा होने के समय होने वाले उत्सव में आशीर्वाद देने और गाने-बजाने के लिए ये आते हैं। ये रेड लाइट पर भी मिल जाते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा और सुना है कि वे हमेशा ताली बजाते रहते हैं। ताली बजाना एक थेरेपी है और यह एक्युपंचर की तरह है। इनको मैंने किसी अस्पताल में नहीं देखा है, आप लोगों ने अगर इनको देखा हो, तो मैं नहीं जानता हूं। ताली बजाने से वे कभी बीमार नहीं होते हैं। यह समाज के लिए एक संदेश भी है। कोई कीर्तन-भजन करते समय ताली बजाता है, तो उससे भी लाभ होता है।

उपसभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे कि हमारी एक केन्द्रीय मंत्री हैं, जो पशुओं के संरक्षण के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ती हैं। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और हम इनसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब पशुओं के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो क्या इन्सान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? ये तो इंसान हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस विषय पर हमारे माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, आप उन पर गंभीरता से विचार करें।

उपसभापति महोदय, बहुत सी और भी दिक्कतें हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले से आदिवासी और दलितों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, इस बारे में हमारे नरेन्द्र कुमार कश्यप जी ने भी बताया है। उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। जो पुरोहित लोग थे, कोई

बच्चा पैदा होता था और उनसे (नामकरण) उन बच्चों के नाम पूछने के लिए जाते थे, अगर वह शैड्यूल्ड कास्ट का है, बैकवर्ड का है, आदिवासी का है, तो पुरोहित लोग कहते थे कि इसका नाम लुच्चा रख दो, इसका नाम लफंगा रख दो, इसका नाम खचेडू रख दो, चैतुवा, बैसखवा, जेठुवा रख दो, यह जेठ में पैदा हुआ है तो जेठुवा रख दो। जब बच्चा स्कूल में जाता था और हाज़िरी लगती थी और जब मास्टर खचेडू, लुच्चा, लफंगा कहता था, तब सारी कक्षा के बच्चे हंसते थे इसलिए वह एक-दो महीने में ही कक्षा छोड़कर चला जाता था। उसी तरह से आज किन्नरों के साथ हो रहा है। हमें महाभारत का भी एक उदाहरण याद है जब वीर एकलव्य शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास गये, क्योंकि वह शूद्र थे, इसलिए उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया कि तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाई जा सकती क्योंकि वे निषाद आदिवासी थे।...(**समय की घंटी**)...उपसभापति महोदय, जब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी न्यायालय कह रहे हैं कि इनके साथ भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... हमारे तिरुची शिवा जी जो बिल लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।...(**समय की घंटी**)... मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बिल से पूरा सदन सहमत है इसलिए आप इस बारे में एक सरकारी बिल लाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं तिरुची शिवा जी की बहुत आभारी हूं कि वे इस बिल को लेकर आए हैं। इस बिल में जो इनकी भावना है वह बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि चाहे हम इन्हें हिजड़ा कहें, चाहे किन्नर कहें, चाहे transgender कहें, इनका जो trauma है, इनका ही नहीं, इनके मां-बाप का जो trauma है, वह भी एक सोचने वाली बात है। जब मां-बाप को पता लगता है कि हमारा बच्चा हिजड़ा है या transgender है और जब उस बच्चे को उस कम्युनिटी वाले लेने के लिए आते हैं, उस समय जो उनका हाल होता है, वह एक देखने की बात होती है। किस तरह से मां अपने बच्चे को अलग करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि माननीय सदस्य जो बिल लाए हैं, वह बहुत ठीक बिल लाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि आप इस बिल का समर्थन कीजिए। इस बिल में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशल व्यवस्था कीजिए, उनको स्पेशल स्कूल दीजिए जिससे कि वे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनको घर-घर जाकर नाचना या गाना न पड़े। यह कोई उनका कसूर नहीं है, यह बायलॉजीकल सबसे बड़ी घटना है, जिसके कारण वे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाए और उनको मेनस्ट्रीम में लाया जाए। यह मां-बाप का भी trauma है, उनका भी दुख है। मैं जानती हूं कि किस तरह से एक मां अपने बच्चे को अपने से अलग करती है। उसके लिए तो वह बच्चा ही है, चाहे वह transgender है या कोई अन्य है। पहले राजा-महाराजाओं के यहां महिलाओं के महल में इनको रखा जाता था कि एक तरह से ये spying का काम करेंगे, इनसे कोई harm नहीं है। जहां आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहां हमें इनके सशक्तिकरण की बात भी करनी चाहिए। ये भी हमारे समाज का एक अंग हैं। मैं तिरुचि शिवा जी को बधाई देती हूं कि वे यह बिल लाए और मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करती हूं कि जिस तरह से इस बिल पर सभी ने कहा है, प्राइवेट मेम्बर बिल देकर वापस मत लीजिए और इसको सरकारी दस्तावेज बनाइए और इस पर बहुत गंभीरता से सोचिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो श्री तिरुची शिवा जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके एक अच्छा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। यह विधेयक निश्चित रूप से विचारणीय है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उसमें एक नहीं अनेक अनुच्छेदों में इस बात का उल्लेख गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक, जो सुविधाएं भारत सरकार की हैं, उनका उपयोग करने के लिए, सुअवसर प्राप्त करने का पात्र है। बिना जाति, बिना लिंग और बिना किसी भेदभाव के उन सब योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। आज हम सदन में किन्नर, विपरीत-लिंग के व्यक्तियों के लिए अधिकार के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इसको Ttransgender नाम दिया है, यह भी हमारे देश के मानव संसाधन का अभिन्न अंग है। देश का अभिन्न अंग होने के नाते, वे समस्त प्रावधान, जो भारत के संविधान में हैं और भारत के कानूनों में हैं तथा राज्यों के कानूनों में हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये अधिकृत हैं। श्री तिरुची शिवा ने विधेयक प्रस्तुत किया है, इस पर श्री बसावाराज पाटिल, श्री हरिवंश, विवेक गुप्ता जी , आदरणीय नवनीत जी, श्री बैष्णव परिडा, श्री पी राजीव जी, श्री डी.पी. त्रिपाठी जी, श्री एम.एस. गिल साहब, श्री मनसुख एल. मांडविया, चौधरी मुनव्वर सलीम, श्री एम.पी. अच्युतन, सुश्री अनु आगा, श्री आनंद भास्कर रापोलू, डा. के. केशव राव, डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन, प्रो. एम. वी. राजीव गौडा, श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और अंत में आदरणीय श्रीमती विप्लव ठाकुर ने अपने विचार रखे हैं। मैं सामान्यतः इस विधेयक की भावनाओं का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में जिन-जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनसे संबंधित मुद्दों की जानकारी अपने-अपने सम्बोधन में दी है। विधेयक को अध्याय 2 किन्नर जाति को, transgender अधिकार और उनकी हकदारियां देने की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि समता और गैर-विभेद का वातावरण बनाना चाहिए। सही बात है, इसका संविधान में भी उल्लेख है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। विपरीतलिंगी बच्चों को भी यह अधिकार मिले। जो सुविधाएँ भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से मिलती हैं, उनका उपभोग करने या उनका लाभ लेने की पात्रता भी उनको होनी चाहिए। उनको जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। मैंने बताया कि ये सब संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में हैं। उनको समुदाय में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, सम्पूर्णता का अधिकार मिलना चाहिए। यातना अथवा निर्दयतापूर्ण, अमानवीय अथवा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार अथवा दंड से उनको संरक्षण मिलना चाहिए। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण का जो वातावरण है, उससे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। घर और परिवार का अधिकार मिलना चाहिए। वाक् स्वातंत्र्य की सुविधा मिलनी चाहिए। अध्याय 3 में शिक्षा के जो अधिकार हैं, उन शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को भी उन्हें प्राप्त करने का हक है, वे भी उनको मिलने चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आदरणीय भूपिंदर जी, मैंने दो घंटे सुना, आप भी 15-20 मिनट तो सुन लीजिए। सुनिए तो सही। कौशल विकास एवं रोजगार की बात भी कही गई है। निश्चित रूप से यह उनका भी अधिकार है कि उनको भी रोजगार मिले और वे स्वावलंबन की स्थिति में आकर अपने आस- पड़ोस वाले लोगों की तरह अपना जीवनयापन, रहन-सहन का स्तर बना सकें। व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार की पात्रता उनको है। रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको

सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ होनी चाहिए। उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। विपरीतलिंगी व्यक्तियों का पुनर्वास सामान्य श्रेणी के लोगों की भाँति हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको विलास संस्कृति और आमोद-प्रमोद की भी पात्रता है, यह उनका हक है, वह भी मिलना चाहिए। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में उनके आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान की बात कही गई है। विपरीतलिंगी व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण की बात कही गई है। निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इनके लिए अलग से विशेष रोजगार कार्यालय हो, इस प्रकार की व्यवस्था की भी बात है। इन सब समस्याओं के समाधान की दृष्टि से सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उन्होंने कहा कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता लाने का भी प्रयास करना चाहिए। फिर विपरीतलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई है। उसी प्रकार के आयोग राज्यों में भी होने चाहिए, इस प्रकार की बात भी कही गई है। निश्चित रूप से न्यायालय की सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए। इसमें जो बातें कही गई हैं, वे आज वास्तव में व्यवहार में दिखाई देती हैं और इससे मुक्ति दिलाने की महती आवश्यकता है। जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, वास्तव में इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस दिशा में एक निर्णय दिया है और उस निर्णय के बाद भारत सरकार ने, अर्थात् मेरे मंत्रालय ने, चूँकि मेरा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में कुछ कदम उठाए हैं। मैं आपके सामने सभी माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराना चाहूँगा। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है। उसने जो प्रतिवेदन दिया है, सामान्यतया प्रतिवेदन में जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों का ज्यादातर समावेश इस विधेयक में है। इसलिए मैं सब पर अलग-अलग कुछ बातें बताऊँ, इसकी आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ ही साथ हमने कार्य योजना बनाने के लिए अंतर-मंत्रालय की एक समिति भी बनाई है और उसकी अभी तक लगभग 4 बैठकें भी हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में तेज गति से विचार-विमर्श जारी है। हमने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाला है कि इसके लिए एक अम्ब्रेला स्कीम बननी चाहिए। वह स्कीम बनाने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं हमारे मंत्रालय के बीच अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श जारी है। हमने एक निर्णय भी लिया है कि इस सम्बन्ध में हम एक राष्ट्रीय नीति बनाएंगे, इसके मुद्दों पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।

महोदय, हमने यह भी तय किया है कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुविधाएं दी जाती हैं, वैसी ही सुविधाएं ट्रांसजेंडर समुदाय को भी दी जानी चाहिए। इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक 'ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड' बनाने का भी विचार किया है। उस 'ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड' के क्या-क्या काम होंगे, क्या-क्या अधिकार होंगे, इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में अमल करने के लिए अनुरोध किया है। हमको अनेक राज्यों से इसकी जानकारी भी मिली है, कई राज्यों ने तो उस पर काम भी प्रारम्भ कर दिया है। जिस प्रकार से योजना आयोग ने इस विषय पर राय दी थी, उसी प्रकार नीति आयोग भी इस पर उसी तारतम्य के आधार पर विचार-

[श्री थावर चन्द गहलोत]

विमर्श करेगा। इस सम्बन्ध में हम इनके अधिकारों के हित संरक्षण की कार्य योजना बनाने का काम भी करेंगे।

इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूंगा, जब हमने भिन्न-भिन्न राज्यों और भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को इस विषय पर लिखा, इस पर उन्होंने जो-जो कार्यवाही की, उससे भी मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा। वैसे प्रारम्भिक तौर पर हमने यह तय किया है, जैसा मैंने बताया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को 'तृतीय लिंगी' के रूप में माना जाए, यह माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों को उनकी बेहतरी के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं तैयार करने हेतु उपाय करने चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को अस्पतालों में ट्रांसजेंडर्स को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए और इनके प्रति सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये सब बिन्दु हमने राज्यों के साथ चर्चा करके उठाए, जिसके लिए हमने उनको पत्र भी लिखा और हमारे अधिकारियों ने उनके साथ बातचीत भी की।

मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने और अगर वे उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी फीस जमा करने, आर्थिक सहायता देने आदि का निर्णय भी लिया है।

महोदय, हमने भारत सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को जो पत्र लिखा था, उसके उत्तर में उनकी ओर से हमारे पास जो जवाब आए हैं, मैं आपको उसकी जानकारी भी देना चाहूंगा। हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था, उनकी तरफ से जवाब आया है कि आवासीय जरूरतों को पूरा करने वाली इन्दिरा आवास योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों को चयन में वरीयता देने के लिए शामिल किया गया है। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में वर्ष 2012-13 के दौरान आईएवाई के तहत 25 आवास ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों ने इस दिशा में कारगर कदम उठाए हैं, उनमें सबसे अच्छा काम तमिलनाडु की सरकार ने किया है। बाकी राज्यों ने भी इस सम्बन्ध में जो-जो कार्य किया है, वह भी मैं बताना चाहूंगा। हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया था, उन्होंने ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने के लिए किशोर न्याय नियमावली, 2007 में संशोधन करने पर विचार प्रारम्भ कर दिया है, साथ ही वैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जिनकी पहचान महिला के रूप में है, को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा कार्यस्थल पर यौन शोषण (निवारण, निषेध तथा निपटान) अधिनियम, 2013 के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाना स्वीकार कर लिया है। वे इस दिशा में कार्यवाही भी कर रहे हैं।

महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटर-सेक्स डिसऑर्डर पर एक समिति का गठन किया है तथा यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित मामलों की जाँच कर रही है।

मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी लिखा। उसने इस पर एक निर्णय लिया है। मानव

संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शैक्षिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रवेश देने के लिए आदेश जारी किये हैं। 'बालक' की परिभाषा के तहत ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में संशोधन पर उन्होंने विचार प्रारम्भ कर दिया है। मंत्रालय समस्त देश में 1090 केन्द्रीय विद्यालयों तथा 581 नवोदय विद्यालयों के संचालन के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। उनको अपनी प्रवेश नीति में ट्रांसजेंडर बच्चों पर विचार करने की भी सलाह दी गई है।

सर, इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय द्वारा यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा विधियों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के समावेशन हेतु आईपीसी की कतिपय धाराओं, जिनका उल्लेख माननीय राजीव गौडा जी ने भी किया था तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया, धारा 317, 166क, 375 इत्यादि में व्यापक संशोधन करने पर भी विचार प्रारम्भ कर लिया गया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने अपने प्रतिवेदनों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित आंकड़े भी शामिल किये हैं।

सर, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। यह विभाग में विचाराधीन है। वे इस पर आगे कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है। शब्द 'जेंडर' को आवेदन पत्रों, प्रतिवेदनों इत्यादि जैसे विभिन्न दस्तावेजों में पुरुष और महिला के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर समाविष्ट करते हुए समाविष्ट कर लिया गया है। अर्थात् इनकी पहचान अलग से करने की व्यवस्था भी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के विस्तार पर विचार किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए असंगठित कार्यकर्ताओं के संबंध में भी प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी कार्य स्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्पीड़न के संबंध में सीसीएस (सीसीए) आचरण नियमावली में संशोधन करने पर विचार किया है। सूचित किया गया है कि सरकारी नियुक्तियों के लिए रोजगार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (हूपा) को भी हमने लिखा था। उसने भी हमें जानकारी दी है और कहा है कि लाभार्थियों के रूप में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटकों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सलाह जारी की गयी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सभी मीडिया एकक, यथा पीआईवी, डीएफपी, एसएनडीडी, एआईआर और डीडी के अपने कार्यक्रमों में इनके हित संरक्षण की योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार करें।

हमने विदेश मंत्रालय से भी आग्रह किया था कि पासपोर्ट देने की जो इनकी कठिनाई है, उसको

[श्री थावर चन्द गहलोत]

भी हल करने का वह प्रयास करे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने से संबंधित नियमों में उपयुक्त संशोधन पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है। उम्मीद है कि वे इस समस्या का समाधान करने में सफलता प्राप्त कर पायेंगे।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों पर नियोक्ताओं और कर्मचारियों को शिक्षित करने और कर्मचारियों को लगाने, बनाये रखने, पदोन्नति इत्यादि के प्रति बिना किसी भेदभाव की नीतियों के लिए विभाग से संबंधित औद्योगिक संगठनों के साथ कार्रवाई की है। अपने फॉर्म प्रपत्रों में ट्रांसजेंडर श्रेणी शामिल करने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली है, मतलब यहां भी उन्होंने उनकी अलग से पहचान करने के लिए नियम बनाने का निर्णय कर लिया है। विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत राज्यों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, we have to finish this Bill today. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, बहुत कुछ बातें आई हैं, तो कम से कम 5-7 मिनट तो और लगेंगे। आप कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to conclude this Bill. ...*(Interruptions)*... Already it has taken more than three hours. ...*(Interruptions)*... The decision is that the Bill should be disposed of in two hours. Now it has taken three hours.

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, मैं 5-7 मिनट लूंगा। अगर आप कहेंगे, तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

श्री उपसभापतिः इनका reply भी होना है।

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, इस संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। सिक्किम राज्य की सरकार ने भी इस विषय पर अच्छा काम करना प्रारंभ किया है। छात्रवृत्ति आदि की जो सब सुविधाएं अन्य नागरिकों को मिलती हैं, वे हैं।

पश्चिमी बंगाल ने भी अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया है और इनकी समस्याओं को हल करना प्रारंभ किया है।

केरल सरकार ने भी किया है। हरियाणा सरकार ने भी किया है। ओडिशा सरकार ने भी किया है। दिल्ली सरकार ने भी किया है। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने भी इस पर कार्य योजना प्रारंभ की है। मैंने बताया कि तमिलनाडु की सरकार ने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जिनका उल्लेख नवनीतकृष्णन जी ने भी किया है और मैं भी कर रहा हूँ।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं तिरुची शिवा जी से और माननीय उन सब सदस्यों से, जिन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया

और कुछ दिशा-निर्देश दिए, उसमें कुछ बातें ऐसी थीं, जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में हमने जो स्पष्टीकरण चाहा है, वह यह है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी ट्रांसजेंडर और स्त्री सजातीय, समलैंगिक और द्विलैंगिक व्यक्तियों के बीच अस्पष्टता उत्पन्न हो रही थी, वह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि उनको किस श्रेणी में लिया जाए। इसलिए इस मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु याचिका दायर की है।

फिर एक महत्वपूर्ण विषय और आया, वह यह कि जब सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी करने की बात कही गई, तो उसमें एक बात आई, हमसे कुछ प्रतिनिधिमंडल भी मिले, इनकी जो ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है, उनकी अखिल भारतीय अध्यक्ष, लक्ष्मी जी भी मिली, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए और उसमें यह बात आई कि अगर कोई जन्म से अनुसूचित जाति का है या जन्म से अनुसूचित जनजाति का है और वह पिछड़ा वर्ग में रहना स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में क्या किया जाए। इस पर मतभेद सामने आए, तो हमने सोचा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ मार्गदर्शन लेना उचित होगा। हमने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है और मैं सोचता हूँ कि जब तक इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण नहीं आए, तब तक इनका identification करने में कठिनाई होगी और जब identification करने में ही कठिनाई होगी, जो अगली कार्य योजनाओं का जो लाभ-हित उनको मिलना चाहिए, उसके बारे में निर्णय करना बहुत कठिन हो जाएगा।

ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय तिरुची शिवा जी से और माननीय अन्य सदस्यों ने, जिन्होंने इस पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय से कुछ मुद्दों पर हमने जो स्पष्टीकरण मांगा है, वह स्पष्टीकरण आ जाए, फिर राज्य सरकारों ने भी कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है। हमने अंतर-मंत्रालयी कमेटी बनाई है, वह भी विचार कर रही है और हमने जो विशेषज्ञ की एक कमेटी बनाई है, उसका जो प्रतिवेदन आया है, उस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। उन अध्ययनों का जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद एक व्यापक विचार-विमर्श करके हम कार्य योजना बनाएंगे। चाहे by laws बना कर इनको हित संरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराएं या बोर्ड बना कर या जो-जो ये विषय हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो-जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उन सब सुविधाओं को देने की हमारी और हमारी सरकार की मंशा है। आप विश्वास करें, हम इनका हित संरक्षण करने की कार्य योजना बनाएँगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में, इन परिस्थितियों में आप अपने इस विधेयक को वापस ले लेंगे, तो बड़ी कृपा होगी। आप सबसे, माननीय सदस्यों से और सदन से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इस दिशा में कारगर कार्रवाई कर रही है, विचार-विमर्श कर रही है और निष्कर्ष निकालकर, इनके हित संरक्षण की कार्य योजना बनाकर इनके हितों को कार्यान्वित करने की योजनाएँ लागू करने पर विचार कर रही है। ऐसी परिस्थिति में आप आज इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I cannot complete within five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the House wants, we can extend and sit. You can speak up to 5.00 p.m. Then, we will continue this Bill next time. You can continue your reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Mr. Siva can speak up to 5 o'clock and then he can continue next time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you can speak Mr. Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, around twenty Members have contributed their valuable suggestions on this Bill. Cutting across party lines, almost all the political parties, which are in this august House, have expressed their views. I am very happy about that. So, there is no difference of opinion, as far as this Bill is concerned. I want to thank all the Members who have deliberated with valuable thoughts and suggestions and have expressed their concerns in favour of the transgender persons. Sir, what induced me to bring this Bill is the fact that the Supreme Court made its historical judgment in the year 2014. The Ministry of Social Justice and Empowerment constituted an Expert Committee, which gave its Report to the Government. Sir, one year has passed by, but nothing is being done. I don't want to repeat what my other colleagues have said here about the discrimination faced by the transgender persons. Sir, every one of us is aware. But how are they treated? Those who express their concern, not in this House but even outside, when they happen to come across one to one, how they treat them is a very big question. Even when the Minister asked me to withdraw my Bill, he said that the Government is committed and has some plans. Sir, we don't want plans. We want legislation in the right place. But for that, there will not be an end to this discrimination.

First of all, Sir, there is a lack of research data about the transgender people in the country and the transgender people specific healthcare. Many of my colleagues have pointed out many experiences they have come across. While moving the Bill, I quoted some incidents that these people don't have access to public toilets. Our colleagues, I think, Tripathiji, said here--and one other colleague also mentioned that a transgender person gets a voter ID card saying that she is a female. Only then is the voter ID card given. But when she enters into a ladies' compartment in a train, she is not given an access. She is just thrown out. So, in every place, whether it is hospital, whether it is a public

5.00 P.M.

place or a toilet or anywhere else, these people are not accepted. So, when fellow persons in our community, for no fault of theirs, are being treated like that, how could it be? But things are changing now. Only in February, 2015, the first passport has been issued, and the issuance of voter ID cards has been started. I would like to say so many words which we do not recognise, like 'hijras', 'kinnars' and many other words too, and now we have all accepted even legally and even those people have accepted this word 'transgender'. So, these transgender people should be given their legitimate right in this country like any other citizen. That is the only concern we want to express. Sir, in this context, I would like to mention one example. The Minister also quoted the example of one Lakshmi. She is from Mumbai and she is the first transgender person to represent the Asia-Pacific at the United Nations in the year 2008. Her autobiography, 'Me Hijra, Me Lakshmi', that is, 'I am Hijra, I am Lakshmi', was released at the just-concluded World Book Fair in Delhi. Her book has been published in Marathi and now has been translated into English by the Oxford University Press. So many eminent people are in the transgender community, but they are denied their rights, they are not being recognised. I think, the Minister has said that we will coordinate with the other Ministries.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Siva, you can continue your speech next time when the Private Members' Bills will be taken up. Now, let us take up further discussion on the Budget (Railways). Shri Avinash Rai Khanna; not present. Shri Mansukh L. Mandaviya.

THE BUDGET (RAILWAYS), 2015-16

श्री मनसुख एल. मांडविया (गुजरात) : उपसभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी जो रेल बजट लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेलवे हमारे देश की धमनी है। 1864 से रेलवे हमारे देश में जन सुविधा का आधार बनी हुई है, ट्रांसपोर्टिंग का आधार बनी हुई है। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में भी और हमारे देश में सामाजिक क्रांति के लिए रेलवे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन**) *पीठासीन हुए*]

रेलवे के माध्यम से हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स और हमारी डाक, हमारे टाट-टपाल सब रेलवे के माध्यम से चलती थी। इसलिए देश की रगों में दौड़ती है रेल, देश के हर अंग को जोड़ती है रेल, देश के हर रंग को जोड़ती है रेल, धर्म, जाति-पांति नहीं जानती है रेल, छोटे-बड़े सभी को अपना मानती है रेल।

---

† Further discussion continned from 12 March, 2015